



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 1993/कार्तिक 27, 1915
No. 403] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 1993/KARTIKA 27, 1915

वित्त मंत्रालय

अनुलग्नक

(राजस्व विभाग)

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और
राजस्व अपव्ययन को रोकने के लिए

अधिमूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1993

भारत गणराज्य की सरकार

आयकर

और

सा.का.नि. 710 (अ) :—यनः आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपव्ययन को रोकने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुए संयुक्त करार को, उक्त करार के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 1 के अनुसार लागू करने के लिए प्रोक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के संबंध में दोनों संबंधकारी राज्यों द्वारा एक-दूसरे को अधिमूचना जारी कर दिए जाने के बाद 22 सितम्बर, 1993 को लागू कर दिया गया है :

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

पारस्परिक आर्थिक संबंधों को उत्तम करने की इच्छा से आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपव्ययन को रोकने के लिए एक करार सम्पन्न करने के लिए तैयारि रखे अनुसार सहमत हुई है :

अनः अथ आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) को धारा 90, कंपनी (अभिलाष) अतिरिक्त अधिनियम, 1964 (1964 का 7) को धारा 24-क और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को धारा 44-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी बनाया जाए ।

अनुच्छेद-10

वैयक्तिक विषय क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दोनों संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद-2

करार के अंतर्गत धाने वाले कर

1. करों के अंतर्गत धान पर तथा पूंजी पर लगने वाले कर प्रायः जिनमें सकल धान पर, सकल पूंजी पर अथवा धान के तत्व पर अथवा पूंजी में मुख्यवृद्धि के साथ-साथ सब अथवा सबल सम्पत्ति के अन्वयण से हुए अभिनामों पर लगने वाले कर सहित पूंजी पर लगने वाले सभी कर शामिल हैं।

2. वे विश्वमान कर, जिन पर यह करार लागू होगा, इस प्रकार हैं :

(क) संयुक्त अरब अमीरात में :

- (1) आय कर;
- (2) निगम कर; और
- (3) धनकर

(जिसका इसके पश्चात् "संयुक्त अरब अमीरात कर" के रूप में उल्लेख किया गया है) ;

(ख) भारत में :

- (1) आयकर पर, जिसमें उपर्युक्त पर चलाया गया कोई अधिभाग शामिल है ;
- (2) अतिकर; और
- (3) धनकर

(जिसका इसके पश्चात् "भारतीय कर" के रूप में उल्लेख किया गया है)

3. यह करार किसी समरूप अथवा मारत इसी तरह की आय अथवा पूंजी के करों पर भी लागू होगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित करों के अनुरूप अथवा उनके समान पर किसी भी संविदाकारी राज्यों द्वारा संघीय अथवा प्रांतीय स्तरों पर लगाये जाते हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किसी भी महत्वपूर्ण परिस्थितियों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अंतर्गत-अंतर्गत कराधान कानूनों में किए जाते हैं।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएँ

1. इस करार में जहाँ-जहाँ कि संदर्भ के अनुसार अथवा श्रद्धा न हो :

(क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है--भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है--अराण्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के साथ-साथ कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिसके बारे में भारत को भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तर-राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रमुखता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार प्राप्त हों;

(ख) "संयुक्त अरब अमीरात" शब्द से अभिप्रेत है संयुक्त अरब अमीरात तथा जब एक भौगोलिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है संयुक्त अरब अमीरात का सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र जिसमें इसका राज्य क्षेत्रीय समुद्र जिस पर संयुक्त अरब अमीरात कराधान से संबंधित कानून के लागू होते हैं तथा इसके समुद्री क्षेत्र से परे कोई भी क्षेत्र जिसके संबंध में संयुक्त अरब अमीरात को अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार इसकी धक्का तथा उर्वरता जल संसाधनों तथा समुद्रमत्त के संसाधनों के उपयोग और अन्वेषण के लिए प्रमुखता सम्पन्न अधिकार प्राप्त हों;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" शब्दों से संदर्भ अथवा के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात अथवा भारत अभिप्रेत है;

(घ) "कर" शब्द से संदर्भ की अथवा के अनुसार अभिप्रेत है "भारतीय कर" अथवा "संयुक्त अरब अमीरात कर", परन्तु इसमें ऐसी कोई एक शामिल नहीं होगी, जो करों के संबंध में किसी भुक्त या भुक्त के संबंध में देय हो जिनके लिए यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्हण्ड को निर्धारित करे हैं;

(ङ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति कंपनी और अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कोई अन्य मत्ता शामिल है जिसे कर-योग्य इकाई के रूप में माना जाता है;

(च) "कंपनी" शब्द से कोई भी ऐसा निर्गमित निवाय अथवा कोई राना अभिप्रेत है जिसे अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कंपनी अथवा निर्गमित निवाय के रूप में माना जाता है;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य या उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य या उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "राष्ट्रिय" शब्द से अभिप्रेत है :

(1) संयुक्त अरब अमीरात के मामले में, वे सभी व्यक्ति जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रियता प्राप्त है तथा कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदार तथा कोई अन्य निर्गमित निवाय जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के तहत ऐसी हैमियत प्राप्त हो;

(2) भारत के मामले में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे भारत की राष्ट्रियता प्राप्त है तथा कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदार तथा संघ जिन्हें भारत में लागू कानूनों के तहत ऐसी हैमियत प्राप्त हो;

(झ) "अन्तरराष्ट्रीय वातावरण" शब्द से अभिप्रेत है किन्तु ऐसे वातावरण अथवा वायुमंडल द्वारा कोई भी परिवहन या एक संविदाकारी राज्य के किसी ऐसे उद्यम द्वारा किया गया किसी संविदाकारी राज्य में प्रवासी प्रवास या स्थापना हो, सिवाय उस स्थिति के कि उक्त जलवायु अथवा वायुमंडल केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही संचालित जाता हो;

(ञ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है :

(1) संयुक्त अरब अमीरात के मामले में, वित्त तथा उद्योग मंत्रालय अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, तथा

(2) भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि।

2. उक्त तब किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के अंतर्गत का संबंध है, किन्ती शब्द का जो उनमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक संदर्भ के अनुसार अथवा श्रद्धा न हो, तब तक यही अर्थ होगा जो उस राज्य के करों में संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है शिवाय यह करार लागू होगा है।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्द से अभिप्रेत है—कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान संस्थापन का स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण, यहाँ पर कर लगाया जा सकता है।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ उसकी हैमियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

- (क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसे कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, तो वह उन राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध अधिकतर (महत्वपूर्ण) हितों का केन्द्र है ;
- (ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित है, निश्चय नहीं किया जा सकता है, अथवा यदि उसके पास दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
- (ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है ;
- (घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के मध्य प्राधिकारी पारस्परिक सहमति के द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध स्थान स्थित है।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" शब्द से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ किसी उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्द में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे।

- (क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कार्यागारा ;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक समाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- (छ) कोई फार्म अथवा बगीचा ;
- (ज) कोई भवन स्थल अथवा निर्माण कार्य अथवा प्रतिष्ठापन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, लेकिन केवल वहाँ जहाँ ऐसा भवनस्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 1) महीने से अधिक अवधि के लिए जारी रहे ;

(झ) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में अपने कर्मचारियों अथवा अन्य कर्मिकों के माध्यम से परामर्शदायी सेवाओं सहित सेवाएँ उपलब्ध कराना, बशर्ते कि ऐसा कार्यकलाप इसी परियोजना हेतु अथवा सम्बन्धित परियोजना हेतु किसी अवधि अथवा अवधियों के लिए जारी रहे जो 12 मास की किसी अवधि में कुल मिलाकर 9 महीनों से ज्यादा हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" शब्द से निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) उद्यम के माल अथवा पथ्य वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) उद्यम के माल अथवा पथ्य वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ ;
- (ग) उद्यम के माल अथवा पथ्य वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव केवल अन्य उद्यम द्वारा प्रसंस्करण हेतु ;
- (घ) उद्यम के लिए केवल माल अथवा पथ्य वस्तुओं का क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करके के प्रयोजनार्थ कारोबार के निदा स्थान का रख-रखाव ;
- (ङ) उद्यम के लिए माल किसी प्राथमिक अथवा सहायक किस्म के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी यहाँ पर कोई स्थान हर्मियन के किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति किसी उद्यम की ओर से कार्य करना हो तथा उसे उस उद्यम की तरफ से उस संविदाकारी राज्य में ठेका का सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो तथा वह आदतन ऐसे ठेके सम्पन्न करता हो। तब उस उद्यम का उस राज्य में ऐसे कार्यकलापों के संबंध में स्थायी संस्थापन तभी माना जाएगा जब ऐसा व्यक्ति उस उद्यम के लिए कार्य करता हो बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा किये जाये गये कार्य उस उद्यम के लिए मान अथवा पथ्य वस्तुओं के खराद तक ही सीमित हों।

5. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में माल इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दवाज, सामान्य कर्मस्थान एजेंट अथवा स्थान हर्मियन वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कार्य करने हो। तथापि, जब ऐसे किसी दवाज के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम के लिए सम्पादित किए जाते हों, तब इस पैराग्राफ के अर्थों के अन्तर्गत उसे स्थान हर्मियन वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 6

अवन सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अवन सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी को आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अवन सम्पत्ति" शब्द का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस शब्द में किसी भी दशा में वे शामिल होंगे—अथवा सम्पत्ति

के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति कृषि तथा वाणिज्य में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिनपर भूमि सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भागने के अधिकार और खनिज भण्डारों, खेतों तथा अन्य प्राकृतिक ससाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नाव तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3 पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाले आय पर भी लागू होंगे।

4 पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबन्ध किसी उद्यम की अवन संपत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

व्यापारिक लाभ

1 किसी सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थान के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार चलाता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हो।

2 पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत रहने वाले जहां एक सविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो, प्रत्येक सविदाकारी राज्य में ऐसे लाभों को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसे उस स्थिति में प्राप्त होने की अपेक्षा रहती है वह एक-समान अथवा उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान अथवा अपने मिलने-जुलने कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होना और उस उद्यम के साथ पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से कारोबार करना जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3 किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन खर्चों को कटौतियों के रूप में अनमति दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार के किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक खर्चों भी शामिल हों, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों, जहां वह स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों।

4 जहां किसी सविदाकारी राज्य में यह प्रथा रही है कि किसी स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभों का निर्धारण उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में विभाजन के आधार पर किया जाता हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस सविदाकारी राज्य को प्रथा अनुसार विभाजन के द्वारा कर योग्य लाभों का निर्धारण करने से निर्वाहित नहीं करेगी। तथापि, विभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसके परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुकूल होंगे।

5 कोई भी ऐसा लाभ मात्र इस कारण से किन स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं।

6 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक वर्तमानवर्ष की पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7 जहां पर लाभों में आय की ऐसी मद शामिल है जिसका इस अभिमतय के अन्य अनुच्छेदों में यथा से निर्धारित है वहां पर उन अनुच्छेदों के उपबन्धों का अनुच्छेद के उपबन्धों में निर्धारित होगा।

अनुच्छेद-8

जहां जरूरी

1 किसी सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

2 इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों का तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा पराग्राफ 1 में उल्लिखित समुद्र द्वारा या विधियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन से प्राप्त लाभ से होगा और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे

(क) ऐसे परिवहन के लिए जलयानों का आनुषंगिक रूप से किराए पर लेना या देना,

(ख) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन के सबन्ध में प्रयुक्त किराए पर लिए गए आधान तथा संबंधित उपस्कर,]]

(ग) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में किसी उद्यम द्वारा परिवहन और स्वामित्व वाले जलयानों, आगगात तथा तबियत उपाकरणों के अन्तरण से प्राप्त लाभ।

3 इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन से संबंधित विधियों पर ब्याज ऐसे जलयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा तथा ऐसे ब्याज के सबन्ध में अनुच्छेद 11 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

4 पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपबन्ध किसी पूत, किसी प्रयुक्त कणोंद्वारा अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-9

राष्ट्रीय उद्यम

जहां कि—

(क) एक सविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रचलन अथवा अप्रत्यक्ष भाग लेता है अथवा

(ख) वे दो व्यक्ति, प्रयोजन अथवा सम्यक्ता एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम में और दूसरे सविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेते हैं और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी बातें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो दोनों शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसे कोई लाभ जो, इन शर्तों के नहीं होने की हालत में, उन उद्यमों में से एक के हाथ हुए किन्तु उन शर्तों के कारण नहीं हुए, तो वे लाभ उन उद्यम के लाभों में परिगणित किए जा सकेंगे और तदनुसार कराधेय हो सकेंगे।

अनुच्छेद-10

लाभांश

1 किसी एक सविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अंश दिए गए लाभांश उन दूसरे राज्य में कराधेय होंगे

2. तथापि, ऐसे लाभों पर सविदाकारी राज्य में भी कर लग सकता है जिस राज्य की लाभों अदा करने वाली कंपनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभों का हिस्सा स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा।

(क) लाभों की सकल रकम का 5 प्रतिशत, यदि द्वितीय भागी स्वामी कोई ऐसी कंपनी है जो लाभों अदा करने वाली कंपनी के कम से कम 10 प्रतिशत शेयरों की स्वामी हो;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभों की सकल रकम का 15 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभों" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय में है, जो लाभ की भागीदारी के ऋण-दायके नहीं हैं और अन्य निर्गमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभों का द्वितीय भागी स्वामी, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में व्यापार करता है जिसकी लाभों अदा करने वाली कंपनी, वहाँ स्थित एक स्थायी स्थापन के माध्यम से निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित आधार से स्थान व्यवस्थित सेवाएँ करता है और जिस धारिता के बारे में लाभों की अदायगी की जाती है, वहाँ इस प्रकार के स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद-14 के उपबन्ध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कंपनी, जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरे राज्य कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभों पर वहाँ तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहाँ तक कि ऐसे लाभों उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हैं अथवा जहाँ तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी स्थापन या किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, यहाँ उस दूसरे राज्य में कंपनी के अनिवार्य लाभों पर अतिरिक्त लाभ संप्रतीक कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभों अथवा अतिरिक्त लाभपूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हो हों।

अनुच्छेद-11

व्याज

1. किसी सविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे व्याज पर उस सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसमें यह उत्पन्न होता है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार होगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का द्वितीय भागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

(क) व्याज की सकल राशि का 5 प्रतिशत, यदि ऐसा व्याज किसी बैंक द्वारा अथवा इसी प्रकार की किसी वित्तीय संस्था द्वारा किसी वास्तविक बैंकिंग कार्य करने पर मजूर किए गए किसी ऋण पर अदा किया जाता है; और

(ख) सभी अन्य मामलों में व्याज की सकल राशि का 12.5 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी सविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले व्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता है और द्वितीय भागी रूप से स्वाभिव्यक्त होता है:

(i) दूसरे सविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनैतिक उप प्रभाव अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा; अथवा

(ii) दूसरे सविदाकारी राज्य के केन्द्रीय बैंक।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "व्याज" शब्द में प्रविष्ट है— प्रत्येक प्रकार के ऋण संप्रतीक दावों में प्राप्त आय, चाहे वे बंधन द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियाँ से प्राप्त आय और राजस्वों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियाँ, बंधनोत्तर अथवा ऋणपत्रों से गारंटी प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। त्रिन्निड में कोई भी अदायगी के लिए आर्थिक-प्रभारों को इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए व्याज नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का द्वितीय भागी स्वामी, सविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे सविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज उत्पन्न होता है, उसमें स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से व्यापार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित आधार से स्थान व्यवस्थित सेवाएँ करता हो और जिस ऋण-दायके के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार से स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबन्ध, जैसी भी स्थिति हो लागू होंगे।

6. व्याज किसी सविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ किसी माना जाएगा जब व्याज अदा करने वाला मध्यम वह सविदाकारी राज्य का राज्य है; कोई राजनैतिक उप-प्रभाव कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी सविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं सविदाकारी राज्य में एक स्थायी स्थापन अथवा एक निश्चित स्थान जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी स्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा उद्भूत किया जाता है तो इस प्रकार का व्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी स्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ व्याज अदाकर्ता तथा द्वितीय भागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष गारंटी हो अथवा होने के कारण अथवा की गई व्याज की रकम उस ऋण-दायके के ध्यान में रखते हुए जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का सबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और द्वितीय भागी स्वामी के बीच सहमति हो गई हो तो वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अतिरिक्त लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस प्रकार के अन्य उपबन्धों का सम्यक् अनुपातन करने हुए, प्रत्येक सविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-12

राजस्थिति

1. एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई राजस्थितियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों उस राज्य के राज्यों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्ति रायल्टियों का डिग्री स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त (रायल्टी) शब्द में सांस्कृतिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियाँ जिनमें चरित्र-चित्रण तथा ऐतिहासिक अथवा दूरदर्शन प्रसारण के संघ में हस्तक्षेप के लिए ऐसे भी शामिल हैं, कोई पेटेंट व्यापारिक डिजाइन, डिजाइन अथवा माटन, प्लान, गुप्त कार्यवाही अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए कानून के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रसिद्धि के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की असाधारण अभिप्रेत है लेकिन इसमें ज्ञानों अथवा ज्ञानों अथवा वैद्युतचुम्बक का उपयोग अथवा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के संबंध में रायल्टी अथवा अन्य असाधारणों शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का लाभकारी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और अथवा संविदाकारी राज्य में निवास रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं, वहाँ पर स्थित स्थायी स्थापना के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस देश राज्य में वहाँ पर स्थित निश्चित आधार से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ करता है तथा जिस प्रक्रिया अथवा संरक्षण के संबंध में रायल्टियों की असाधारण की जाती है उसके संबंध में प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार से है। ऐसे मामले में क्या-स्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 11 के उपबंध लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टी तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायल्टी करने वाला रथम वह राज्य, उनका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहाँ रायल्टी अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टी अदा करने का वजन दिया गया हो और ऐसी रायल्टी उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टी उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहाँ असाधारणों और डिग्री स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों इसके उपयोग, अधिभार तथा सूचना, जिनके लिए इसकी असाधारणों की गई थी, उस रकम से बच जाती है जिनकी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने को स्थिति में असाधारणों तथा लाभ-भोगी स्वामी के बीच सहमति हुई होगी, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम अर्थात् रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर इस प्रकार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के राज्यों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-13

सूचीयत अभिप्राय

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित पञ्चम सम्पत्ति के अन्तर्गत में एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिप्रायों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी पञ्चम सम्पत्ति के अन्तर्गत से हानि वाले अभिप्रायों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी पञ्चम-संपत्ति के अन्तर्गत से होने वाले अभिप्रायों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (पेटेंट अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तर्गत से होने वाले अभिप्राय भी शामिल हैं उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त अभिप्रायों पर उन्हीं संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तर्गतकरण निवासी है।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वतंत्र होने वाली तरीके के या कारागारों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होंगी:

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उसी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अस्थिरता संलग्न "छोटे वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उससे अधिक हों, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होनी हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएँ" शब्द के अन्तर्गत स्वतंत्र वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद-15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएँ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, नियोजन के संबंध में, अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राप्त वेतनों, मजूरियों और अन्य इस प्रकार के पारिश्रमिक पर कर, यदि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है तो, केवल उसी राज्य में लगेगा परन्तु यदि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, तो उसे पारिश्रमिक वहाँ से प्राप्त हुआ हो, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोलिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

[(क) वहां संगन "पिछले वर्ष" अथवा "पाय वर्ष" के दौरान ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रखा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है, जैसा भी मामला हो;

[(ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से भुकाया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

[(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी स्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान द्वारा बहुत नहीं किया जाता है जो नियोजक के दूसरे राज्य में हो।

3. उस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी अन्तरराष्ट्रीय सातत्यता में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित पोत अथवा विमान पर रिये गये नियोजन के उस संबंध में पारिश्रमिक पर कर केवल उसी संविदाकारी राज्य में लगाने जा सकेगा।

अनुच्छेद-16

निदेशकों की फीस

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की हैमियन से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद-17

मनोरंजनकर्ताओं और ऐश्वरीयों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी ऐश्वरीय के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यक्रमों में प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी ऐश्वरीय द्वारा अपनी इस प्रकार की हैमियन में किए गए वैयक्तिक कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या ऐश्वरीय को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा ऐश्वरीय के कार्यक्रमों पर किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी ऐश्वरीय द्वारा, जो एक सरकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैमियन में किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों से अर्जित आय प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, जब दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यक्रमों प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य की जिसमें उसके राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सार्वजनिक विधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्पित होते हैं।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 14 तथा 15 के उपबंधों के होते हुए भी जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी ऐश्वरीय द्वारा उसी हैमियन में एक संविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त आय मनोरंजनकर्ता अथवा स्वयं ऐश्वरीय को प्राप्त नहीं होती है परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल

दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि वह व्यक्ति, जिसमें उसके राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सार्वजनिक विधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्पित होता हो।

अनुच्छेद-18

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के निमित्त प्रदान पेंशन से भिन्न, पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा,

(ख) लेकिन, ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो :

(i) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना था।

2 (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा मुजिन किए गए बोप में से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदान किसी पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।

(ख) लेकिन, ऐसी पेंशन पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि व्यक्ति उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16 तथा 17 के उपबंधों में संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारोबार के निमित्त में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-19

गैर-सरकारी पेंशन तथा वार्षिकी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्त्रोतों से प्राप्त अनुच्छेद 14 में उल्लिखित किसी पेंशन से भिन्न किसी पेंशन अथवा किसी वार्षिकी पर कर प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में लगेगा।

2. "पेंशन" शब्द में निम्नो सेवाओं के लिए प्रतिकर के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जा सकने वाली प्राप्ति शामिल होगी।

3. "वार्षिकी" शब्द में अभिप्राय धन अथवा धन के मूल्य के रूप में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिकर के एवज में अदायगी करने के दायित्वों के अध्याधीन जीवनपर्यन्त अथवा किसी निर्दिष्ट अथवा निश्चित गगनराशि के दौरान निश्चित समय पर शाश्वत आधार पर निश्चित राशि की अदायगी से है।

अनुच्छेद-20

विद्यार्थी, शोधार्थी तथा शोध

1. कोई व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में विद्यार्थी के रूप में या किसी माध्यम-प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था में अस्थायी रूप से उपस्थित हो अथवा उन दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके

प्रथम आगमन की तारीख से 6 वर्षों से अधिक अवधि के लिए, यहाँ पर तकनीकी प्रशिक्षण के रूप में आरम्भ व्यवसाय के संबंध में दूसरे संविदाकारी राज्य के अध्यायी रूप से विद्यमान है, तो निम्नलिखित पर उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी :

- (क) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रथमोन्लिखित संविदाकारी राज्य से प्रेषित राशियाँ रकमों और
- (ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए उसे उपलब्ध संसाधनों की वृद्धि की वृष्टि से उस संविदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक सेवाओं के लिए पारिश्रमिक (प्रति वर्ष 20,000 भारतीय रुपयों अथवा यू.ए.ई. मुद्रा में उनके समतुल्य रकम से अधिक हो) ।

2. कोई व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य से अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में अध्यायी रूप से विद्यमान है तथा जो दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों से प्राप्त अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार अथवा वैज्ञानिक, शैक्षिक धार्मिक अथवा धर्मार्थ संगठनों से प्राप्तकर्ता के रूप में अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकार द्वारा लागू किसी तकनीकी महायत्ना कार्यक्रम के अंतर्गत उसके टहरने के संबंध में उस दूसरे संविदाकारी राज्य से उसके प्रथम आगमन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि अवधि के लिए उसे उससे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी

- (क) ऐसे अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार की रकम पर ;
- (ख) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रथमोन्लिखित संविदाकारी राज्य से प्रेषित सभी रकमों पर ; तथा
- (ग) उस अन्य संविदाकारी राज्य में की गई सेवाओं के संबंध में कोई पारिश्रमिक (प्रति वर्ष 20,000 भारतीय रुपयों अथवा यू.ए.ई. मुद्रा में उनके समतुल्य रकम से अधिक नहीं), यदि ये सेवाएँ उसके अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण अथवा प्रसंगवश निष्पादित की गई हों ।

3. जो व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में अध्यायी रूप से प्रथम उन्लिखित राज्य में किसी उद्यम के किसी कर्मचारी के रूप में अथवा उसके साथ अनुबंध के अधीन ऐसे उद्यम से भिन्न किसी व्यक्ति से तकनीकी व्यावसायिक अथवा व्यवसाय संबंधी अनुभव निर्मित करने के प्रयोजन से उस दूसरे राज्य से ऐसी अवधि के लिए जो 12 माह से अधिक नहीं है, उपस्थित रहता है तो उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी —

- (क) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रथम उन्लिखित संविदाकारी राज्य से प्रेषित सभी रकमों पर ; और
- (ख) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक सेवाओं के किसी पारिश्रमिक पर यह प्रति वर्ष 20,000 भारतीय रुपयों अथवा यू.ए.ई. की मुद्रा में उसके समतुल्य रकम से अधिक नहीं हो बशर्ते ऐसी सेवाएँ ऐसे अनुभव की प्राप्ति के संबंध में की गई हों ।

4. कोई व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो मात्र प्रशिक्षण अथवा अध्ययन के प्रयोजन के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य में अध्यायी रूप से विद्यमान है, ऐसे प्रशिक्षण अथवा अध्ययन के कारण उसे प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से मुक्त होगा ।

5. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनों के लिए

- (क) (i) किसी व्यक्ति को भारत का निवासी नब माना जाएगा यदि वह भारत में उस पूर्ववर्ती वर्ष अथवा "पूर्ववर्ती वर्ष" से तत्काल के पूर्ववर्ष में निवासी है जिसमें वह यू.ए.ई. में आता है ।
- (ii) कोई व्यक्ति यू.ए.ई. का निवासी नब माना जाएगा जब भारत आने से तत्काल पूर्व वह यू.ए.ई. का निवासी है ;
- (ख) किसी संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल अथवा अन्य शैक्षणिक संगठन के राज्य में पर "मान्यता-प्राप्त" मन्दिर की स्थिति में उस राज्य के मन्त्र प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

अनुच्छेद-21

प्रोफेसर अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई व्यक्ति जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करे से तत्काल पूर्व एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी ऐसी ही शैक्षिक संस्था जो किसी सरकार, किसी राजनीतिक उपग्राम अथवा उस राज्य के किसी स्थानीय अथवा माविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो के नियंत्रण पर ऐसी शैक्षिक संस्थाओं में केवल शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए उस संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, उसे ऐसे अध्यापक अथवा अनुसंधान के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद ऐसे अनुसंधान से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान मुख्यतः किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो ।

अनुच्छेद-22

आय आय

1. पैराग्राफ 2 उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मर्यादों पर, जहाँ-कहीं से उत्पन्न होती हों जिन पर इन करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया हो, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैरा 2 में यथा-परिभाषित आय संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय को प्राप्त करने वाला किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थान के माध्यम से उस संविदाकारी राज्य से व्यापार चलाता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ निष्पन्न करता है, वह अधिकार अथवा संपत्ति जिसके संबंध में आय का भूमागत किया जाता है, प्रचाली तौर पर ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से संबंधित है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो लागू होंगे ।

अनुच्छेद-23

पुत्री

1. अनुच्छेद 6 में उन्लिखित अवल संपत्ति द्वारा निम्नित पुत्री पर जो कि एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्वामित्व में हो तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

2. एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति के अंग के रूप में चल सम्पत्ति द्वारा अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति द्वारा जो एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे सविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, निरूपित पूँजी पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिणामित जलयानों तथा ऐसे जलयानों के प्रचालन में संबंधित घन संपत्ति द्वारा निरूपित पूँजी उस सविदाकारी राज्य में ही कगधेय होगी, जिसमें कि उद्यम के प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद-24

सरकार और सस्याओं की प्राय

1. किसी एक सविदाकारी राज्य की सरकार को दूसरे सविदाकारी राज्य में उस सरकार द्वारा प्राप्त की गई प्राय के सबंध में दूसरे सविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रयोजनों के लिए "सरकार" शब्द का अर्थ है —

(क) भारत के मामले में इसका अर्थ है कि भारत की सरकार तथा इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (i) राजनीतिक उपप्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकार ;
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक ;
- (iii) ऐसा ही कोई संस्थान अथवा निकाय जिसके बारे में दोनों सविदाकारी राज्यों के बीच समय-समय पर सहमति हो ;

(ख) संयुक्त अरब अमीरात के मामले में इसका अर्थ संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से है तथा उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (i) राजनीतिक उपप्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकार ;
- (ii) संयुक्त अरब अमीरात का सेंट्रल बैंक आबु-धाबी इन्वैस्टमेंट अथॉरिटी तथा आबु-धाबी फंड फार इकनामिक डिवेलपमेंट ;

(iii) ऐसा ही कोई संस्थान अथवा निकाय जिसके बारे में दोनों सविदाकारी राज्यों के बीच में समय-समय पर सहमति हो।

अनुच्छेद-25

दोहरे कराधान का अपाकरण-

1. दोनों सविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित सविदाकारी राज्य में प्राय और पूँजी के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ पर इस प्रकार में उनके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाता है।

2. जहाँ पर भारत का कोई निवासी ऐसी प्राय प्राप्त करता है अथवा पूँजी का स्वामित्व रखता है जिस पर इस प्रकार के उपबंधों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में कर लगाया जा सकता है उस स्थिति में भारत उस निवासी को उस प्राय पर कर से कटौती की अनुमति उतनी राशि के बराबर देगा जितनी राशि की अवायगी संयुक्त अरब अमीरात में कर के लिए की गई हो, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो अथवा

कटौती के द्वारा भी गई हो और उस निवासी को पूँजी पर से कर में कटौती की अनुमति उतनी राशि के बराबर देगा जितनी राशि की अवायगी संयुक्त अरब अमीरात में कर के लिए की गई हो। किसी भी मामले में ऐसी कटौती की राशि प्रायकर अथवा पूँजी कर (कटौती किए जाने से पूर्व यथा संगणित) के उतने भाग से अधिक नहीं होगी जो यथा-स्थिति उस प्राय अथवा पूँजी के कारण उत्पन्न हुई हो जिस पर संयुक्त अरब अमीरात में कर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, जहाँ ऐसा निवासी एक कंपनी है जिसके द्वारा भारत में अतिरिक्त देय हो, वहाँ संयुक्त अरब अमीरात में प्रदा किए गए प्रायकर के सबंध में कटौती की अनुमति प्रथमतया उस कंपनी द्वारा भारत में देय प्रायकर से दी जाएगी और गेप एकम पर, यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में देय अतिरिक्त की अनुमति दी जाएगी।

3. संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के अंतर्गत जहाँ संयुक्त अरब अमीरात का कोई निवासी प्राय प्राप्त करता है जिस पर इस प्रकार के उपबंधों के अनुसार कर लगाया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात उस व्यक्ति द्वारा भारत में प्राय पर प्रदा किए गए कर के बराबर प्राय पर कटौती की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती, कटौती की अनुमति दिए जाने से पूर्व प्रायकर की संगणना से पूर्व प्राय कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिस पर संयुक्त अरब अमीरात में कर लगाया जा सके।

4. पैराग्राफ 3 के प्रयोजन के लिए "भारत में प्रदा किया गया कर" शब्द में भारतीय कर की वह राशि शामिल समझी जाएगी जिसकी उस ह्रास में अवायगी कर की गई होती यदि भारतीय प्रायकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन उपायों के अनुसार भारतीय कर पर छूट न दी गई होती अथवा इसमें कमी न कर दी गई होती, वे उपाय जो कि भारत में आर्थिक विकास के लिए तैयार किए गए हैं इस प्रकार पर हस्ताक्षर की तारीख से लागू होंगे अथवा भारत में आर्थिक विकास के सर्वधन के लिए विद्यमान उपबन्धों में संशोधन अथवा परिवर्धन के लिए और ऐसे अन्य प्रोत्साहन वाले उपाय, जो कि सविदाकारी राज्यों के द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए जाएंगे, भविष्य में लागू किए जा सकते हैं।

5. जहाँ, इस प्रकार के किसी भी उपबन्ध के अनुसार एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त प्राय अथवा स्वामित्व वाली पूँजी को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त है, फिर भी ऐसा राज्य, ऐसे निवासी को शेष प्राय अथवा पूँजी पर कर की संगणना करने समय, इस प्रकार छूट प्राप्त प्राय अथवा पूँजी का ह्रास में रखेगा।

अनुच्छेद-26

सम-अवहार

1. एक सविदाकारी राज्य के राष्ट्रको पर दूसरे सविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्समवर्ती ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भार-पूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रको पर समान परिस्थितियों में और एक-समान शर्तों पर लागू होती है अथवा लागू हो सकती है।

2. एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे सविदाकारी राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों में तथा एक-समान शर्तों के अधीन समान कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. इस अनुच्छेद के उपबन्धों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक सविदाकारी राज्य दूसरे सविदाकारी राज्य के निवासियों को उनके किसी सिविल ओहदे (दर्जे) अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण

कराधान के प्रयोगों के लिए कोई निजी छूटें, राहतें और कटौतियां प्रदान करेगा जो कि वह अपने निशानियों को प्रदान कर रहा है।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निकायों से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमान्वित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा सम्बंधी कोई ऐसा अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और सम्बंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमान्वित राज्य के अन्य समान उद्यमों पर समान परिस्थितियों और परिणामों के अधीन लागू हैं अथवा लागू हो सकती हैं।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद से वे कर अभिप्रेत हैं, जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद-27

पारस्परिक कार्याविधि

1. जहां कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है अथवा लगाया जाएगा जो उस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रख सकता है जिसका वह निवासी है। यह मामला उस कार्य की सूचना प्राप्ति की तारीख से दो वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस के कारण उस करार के उपबंधों के अनुरूप कर नहीं लगा है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक ढाल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो ऐसे कराधान के परिहार की वृष्टि, जो इस करार के अनुरूप नहीं है दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति के द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किया गया कोई भी समझौता किसी तरह की समय-सीमा पर ध्यान न देने हुए संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों के तहत, कार्यान्वित किया जाएगा।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई भिन्नताएं अथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। जब करार को निष्पन्न करने के लिए विचार-विमर्श करने की आवश्यकता हो, तो विचारों का ऐसा आदान-प्रदान एक उच्च आयोग के माध्यम से हो सकता है जिसमें दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी हों। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी व्याख्या इस करार में नहीं दी गई है।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस करार को लागू करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

अनुच्छेद-28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों के कार्यान्वयन अथवा उन करों के अपवर्जन की रोकथाम अथवा पता लगाने के लिए, जो कि इस करार के विषय हैं, आवश्यक हैं। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना गुप्त मानी जाएगी, परंतु केवल ऐसे व्यक्तियों (किन्हीं अदालत अथवा प्रशासनिक निकाय सहित) को बताई जा सकती है जो उन करों के संबंध में कर-निर्धारण, वसूली, प्रवर्तन, जीव अथवा अभियोजन से संबंधित है जोकि इस करार के विषय हैं अथवा उन व्यक्तियों को, जिनसे यह सूचना संबंध रखती है।

2. किन्हीं विशिष्ट मामलों के संदर्भ में अनुरोध प्राप्त होने पर भी सूचना का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित उत्तरदायित्व डाला जाए :

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त ज्ञेय अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती है, (जिसको प्रकट करना सरकार की मोति ग्राहंरि पब्लिक) के प्रतिकूल है।

अनुच्छेद-29

राजनयिक तथा कामुसी क्रियाकलाप

इस करार की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कामुसी अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत दिए किए जितनी विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-30

प्रवर्तन

प्रत्येक संविदाकारी राज्य, इस करार को लागू करने के लिए अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित कार्रवाहियों को पूरा करने के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा। इन अधिसूचनाओं के पत्र प्राप्त होने की तारीख से यह करार लागू होगा और इस प्रकार यह प्रभावी होगा—

(क) संयुक्त अरब एमीरात में :

उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें यह करार लागू होता है, के अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके पश्चात् प्राप्त की गई आय के संबंध में और उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें यह करार लागू होता है अथवा अनुवर्ती वर्षों में भारत अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के समाप्त होने पर भारत पूंजी के संबंध में;

(ख) भारत में :

उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें यह करार लागू होता है, के अगले अनुवर्ती वर्ष की प्रथम अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में और उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें यह करार लागू होता है, से अगले अनुवर्ती वर्ष की प्रथम अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले "पूर्ववर्ती वर्ष" के समाप्त होने पर भारत पूंजी के संबंध में।

अनुच्छेद-31

समाप्ति

यह करार अनिश्चित काल के लिए लागू रहेगा लेकिन दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की तीस जून को अथवा उससे पहले राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को उसकी समाप्ति का लिखित रूप से नोटिस दे

सकेंगे। ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा

(क) संयुक्त अरब एमीरात में

जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति की सूचना दी जाती है उसमें अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके पश्चात् प्राप्त की गई आय के संबंध में और जिसे कैलेंडर वर्ष में समाप्ति की सूचना दी जाती है उसमें होने अनुवर्ती वर्ष अथवा अनुवर्ती वर्षों के अंत में धारित पूंजी के संबंध में,

(ख) भारत में

जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति की सूचना दी जाती है उसमें अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली अप्रैल अथवा उसके पश्चात् प्राप्त की गई आय के संबंध में और जिसे कैलेंडर वर्ष में समाप्ति की सूचना दी जाती है उसमें अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् प्राप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में धारित पूंजी के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में एक हजार नौ सौ बयानवे के अश्विन मास के बुधवार 29वें दिन तबनुमार शब्दाल 1412 हिजरी के 27वें दिन हिन्दी, अरबी, अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल पाठों में सम्पन्न किया गया, इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। इन पाठों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य का सरकार
की ओर से

संयुक्त अरब अमीरात की
सरकार की ओर से

ह०/-

ह०/-

(मनमोहन सिंह)

(हमदान बिन रशीद अल सक्तूम)

वित्त मंत्री

वित्त तथा उद्योग मंत्री

प्रोक्षक

प्राप्त तथा पूंजी पर करों के संबंध में बाह्य कराधान के परिहार और राजस्व के अपव्यय को रोकने के लिए संयुक्त अरब एमीरात की सरकार और भारत गणराज्य का सरकार के बीच में प्राप्त करने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, ऐसे विवादों पर संयुक्त अरब एमीरात का कानून लागू होगा।

(1) अनुच्छेद 5 के उपबन्धों के अनुसरण में इस करार से संयुक्त अरब एमीरात, इसके राजनैतिक उपप्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा स्थानीय सरकारें पेट्रोलियम और प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त की गई आय पर कराधान में संबंधित अपने कानूनों को लागू करने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, ऐसे विवादों पर संयुक्त अरब एमीरात का कानून लागू होगा।

(11) अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 23 के उपबन्ध के होते हुए भी एक सविशकारी राज्य के किसी राष्ट्रिक के द्वारा दूसरे सविशकारी राज्य में अपने स्वामित्व में रखी गई आवासीय संपत्ति पर जो कि उसने अपने घोषण के लिए रखी हुई है, दूसरे सविशकारी राज्य में इस करार में शामिल करों से छूट प्राप्त होगी,

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में एक हजार नौ सौ बयानवे के अश्विन मास के बुधवार 29वें दिन तबनुमार शब्दाल 1412 हिजरी के 27वें दिन हिन्दी, अरबी, अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल पाठों में सम्पन्न किया गया, इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। इन पाठों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य का सरकार
की ओर से

संयुक्त अरब अमीरात की
सरकार की ओर से

ह०/-

ह०/-

(मनमोहन सिंह)

(हमदान बिन रशीद अल सक्तूम)

वित्त मंत्री

वित्त तथा उद्योग मंत्री

[सं० 9403/का०सं० 501/1/39-एकटीडी]

बोर्डींग प्रतिवाचन, गणराज्य संघ

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 1993

INCOME-TAX

G.S.R. 710(E).—Whereas the annexed agreement between the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has entered into force on the 22nd September, 1993 after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the proceedings required by laws for bringing into force of the said agreement in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the said agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), Section 24A of the Companies, (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and Section 44A of the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said agreement shall be given effect to in the Union of India

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates.

Desiring to promote mutual economic relations by concluding an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital.

Have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital including taxes on gains from alienation of movable or immovable property as well as on capital appreciation.

2. The existing taxes to which the Agreement shall apply are :

(a) In United Arab Emirates :

(i) income tax;

(ii) corporation tax;

(iii) wealth tax

(hereinafter referred to as "U.A.E. tax");

(b) In India :

(i) the income-tax including any surcharge thereon;

(ii) the surtax; and

(iii) the wealth tax

(hereinafter referred to as "Indian tax").

3. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes on income or capital which are imposed at Federal or State level by either Contracting State in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 2 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires .

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the India law and in accordance with international law;

(b) the term "U.A.E." means the United Arab Emirates and when used in a geographical sense, means all the territory of the United Arab Emirates including its territorial sea

in which the U.A.E. laws relating to taxation apply and any area beyond its territorial sea within which the United Arab Emirates has sovereign rights of exploration for and exploitation of resources of the seabed and its sub-soil and superjacent water resources in accordance with international law;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean U.A.E. or India as the context requires;

(d) the term "tax" means "Indian tax" or "U.A.E. tax" as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;

(e) the term "person" includes an individual, a company, and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(g) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "national" means :

(i) in the case of U.A.E. all individuals possessing the nationality of U.A.E. in accordance with U.A.E. laws and any legal person, partnership and other body corporate deriving its status as such from U.A.E. laws;

(ii) in the case of India, any individual possessing the nationality of India and any legal person, partnership, or association deriving its status as such from the laws in force in India;

(iii) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(j) the term "competent authority" means :

(i) in the case of U.A.E, the Minister of Finance and Industry or his authorised representative; and

- (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domestic residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (2) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a farm or plantation;

(h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activity continues for a period of more than 9 months;

(i) the furnishing of services including consultancy services by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel in the other Contracting State, provided that such activities continue for the same project or connected project for a period or periods aggregating more than 9 months within any twelve-month period.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise,
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies—is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats, and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the methods of apportionment adopted shall however be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by the permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation by that enterprise of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea of passengers, mail, livestock or goods and shall include:

- (a) the charter or rental of ships incidental to such transportation;
- (b) the rental of containers and related equipments used in connection with the operation of ships in international traffic;
- (c) the gains derived from the alienation of ships, containers and related equipments owned and operated by the enterprise in international traffic.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ship and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least ten per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 5 per cent of the gross amount of the interest if such interest is paid on a loan granted by a bank carrying on a bonafide banking business or by a similar financial institution ; and
- (b) 12.5 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :—

- (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State ; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures including premiums and prizes attaching to such securities, bonds, or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provision of this Article shall apply only to the past-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being due to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of such royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payment of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience but do not include royalties or other payments in respect of the operation of mines or quarries or exploitation of petroleum or other natural resources.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the

royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in paragraph 2 of Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1 and 2 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State, except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed regularly available to him, in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; in that case only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 & 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2657 GI/93—3

Article 17

INCOME EARNED BY ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Article 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or an athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

Article 18

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

Article 19

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 18, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20

STUDENTS, TRAINEES AND APPRENTICES

1. An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State solely as a student at a recognised university, college, school or other educational institution in that other Contracting State or as a business or technical apprentice therein, for a period not exceeding six years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit, shall be exempt from tax in that other Contracting State on—

(a) all remittances from the first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training; and

(b) any remuneration (not exceeding 20,000 Indian rupees or its equivalent sum in UAE currency per annum) for personal services rendered in that other Contracting State with a view to supplementing the resources available to him for such purposes.

2. An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in other Contracting State for the purpose of study, research or training solely as a recipient of a grant, allowance or award from the Government of either of the Contracting States or from a scientific, educational, religious or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of either of the Contracting States for a period not

exceeding three years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit shall be exempt from tax in that other Contracting State on—

(a) the amount of such grant, allowance or award;

(b) all remittances from the first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training; and

(c) any remuneration (not exceeding 20,000 Indian Rupees or its equivalent sum in UAE currency per annum) in respect of services in that other Contracting State if the services are performed in connection with his study, research, training or are incidental there to.

3. An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State solely as an employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of acquiring technical, professional or business experience from a person other than such enterprise, for a period not exceeding twelve months from the date of his first arrival in the other Contracting State in connection with that visit shall be exempt from tax in that other Contracting State on—

(a) all remittances from the first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training; and

(b) any remuneration, so far as it is not in excess of 20,000 Indian Rupees or its equivalent sum in UAE currency per annum, for personal services rendered in that other Contracting State, provided such services are in connection with the acquisition of such experience.

4. An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State under arrangements with the Government of that other Contracting State solely for the purpose of training or study shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration received by him on account of such training or study.

5. For the purposes of this Article and Article 21,

(a) (i) an individual shall be deemed to be a resident of India if he is resident in India in the 'previous year' in which he visits UAE or in the immediately preceding 'previous year';

(ii) an individual shall be deemed to be a resident of UAE if, immediately before visiting India, he is a resident of UAE;

(b) the term "recognised" in relation to a university, college, school or other educational institution in a Contracting State shall, in the case of doubt, be determined by the competent authority of that State.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

1. An individual who is a resident of a Contracting State, immediately before making a visit to the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, college, school or other similar educational institution, which is recognised by the Government, a political subdivision or a local or statutory authority of that State, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching or research or both at such educational institution, shall be exempt from tax in that other Contracting State on his remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2657 GI/93-4

Article 24

INCOME OF GOVERNMENT AND INSTITUTIONS

1. The Government of one of the Contracting States shall be exempt from tax in the other Contracting State in respect of any income derived by such Government from that other Contracting State.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, the term "Government"—

(a) in the case of India, means the Government of India, and shall include :

(i) the political sub-divisions, the local authorities, the local administrations, and the local governments;

(ii) the Reserve Bank of India;

(iii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States;

(b) in the case of UAE, means the Government of the United Arab Emirates, and shall include :

(i) the political sub-divisions, the local authorities, the local administrations, and the local governments;

(ii) The Central Bank of the United Arab Emirates, Abu Dhabi Investment Authority and Abu Dhabi Fund for Economic Development;

(iii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States.

Article 25

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting States except where express provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in U.A.E., India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income-tax paid in U.A.E. whether directly or by deduction; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in U.A.E. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income-tax or capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in U.A.E. Further, when such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income-tax paid in U.A.E. shall be allowed in the

first instance from income-tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from the surtax payable by it in India.

3. Subject to the laws of the U.A.E. where a resident of the UAE derives income which in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in India, the UAE shall allow as a deduction from the tax on income of that person an amount equal to the tax on income paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in the UAE.

4. For the purpose of paragraph 3, the term 'tax paid in India' shall be deemed to include the amount of Indian tax which would have been paid if the Indian tax had not been exempted or reduced in accordance with the special incentive measures under the provisions of the Income-tax Act, 1961, which are designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Agreement, or which may be introduced in the future in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting economic development in India, and such other incentive measures which may be agreed upon from time to time by the Contracting States.

5. Where, in accordance with any provision of the Agreement, income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may, nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

Article 26

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that Contracting State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

3. The provisions of this Article shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the

first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within two years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinion, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of applying this Agreement.

Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or for the prevention or detection of evasion of taxes which are the subject of this Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed only to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or to persons with respect to whom the information relates.

2. The exchange of information may also be on request with reference to particular cases.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation;

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the proceedings required by its law for the bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect—

(a) in the United Arab Emirates :

in respect of income derived on or after the 1st January next following the calendar year in which the Agreement enters into force and in respect of capital which is held at the expiry of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force or subsequent years;

(b) in India :

in respect of income arising in any 'previous year' in beginning on or after 1st April next following the calendar year in which the Agreement enters into force and in respect of capital which is held at

the expiry of any previous year' beginning on or after 1st April next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

Article 31

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such event, the Agreement shall cease to have effect—

(a) in the United Arab Emirates :

in respect of income derived on or after 1st January next following the calendar year in which the notice of termination is given and in respect of capital which is held at the expiry of the calendar year next following that in which the notice of termination is given or subsequent years;

(b) in India :

in respect of income arising in any 'previous year' beginning on or after 1st April next following the calendar year in which the notice of termination is given and in respect of capital which is held at the expiry of any 'previous year' beginning on or after 1st April next following the calendar year in which the notice of termination is given,

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in two originals at New Delhi on this Wednesday 29th day of April One Thousand Nine Hundred and Ninety Two corresponding to the 27th day of Shawwal 1412 H in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence amongst the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of
The REPUBLIC OF INDIA

Sd/-

(Manmohan Singh)
Minister of Finance

For the Government of
The UNITED ARAB EMIRATES

Sd/-

(Hamdan Bin Rashid Al Maktoum)
Minister of Finance & Industry.

PROTOCOL

At the signing today of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of this Agreement :

- (i) Subject to the provisions of Article 5, nothing in this Agreement shall affect the right of the Government of the United Arab Emirates, its political sub-divisions, local authorities or local Governments to apply its own laws related to the taxation of income derived from the petroleum and natural resources; such activities will be taxed according to the laws of the United Arab Emirates;
- (ii) Notwithstanding the provisions of Article 6 and Article 23, the residential property owned by a national of a Contracting State and occupied for self-residence in the other Contracting State shall be exempt in the other Contracting State from the taxes covered by the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. '

Done in two originals at New Delhi on this Wednesday 29th day of the April One Thousand Nine Hundred and Ninety Two corresponding to the 27th day of Shawwal 1412 H in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equal authentic. In case of divergence amongst the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of
The REPUBLIC OF INDIA

Sd/-
(Monmohan Singh)
Minister of Finance

For the Government of
The UNITED ARAB EMIRATES

Sd/-
(Hamdan Bin Rashid Al Maktoum)
Minister of Finance & Industry
[No. 9409/F. No. 501/3/89-FTD]
V. B. SRINIVASAN, Jt. Secy.